खबर संक्षेप

मलेरिया जागरुकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना

शहडोल। मलेरिया निरोधक माह जून 2026 के अवसर जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ. एस.डी. कवर द्वारा मलेरिया रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना। मलेरिया रथ जिले के समस्त विकासखण्ड एवं शहरी क्षेत्र के मलेरिया प्रभावित, पहुंचविहीन, सीमावर्ती ग्रामों, पचांयतों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हाट-बाजार में भ्रमण कर मलेरिया, डेंगू एवं अन्य वाहक जनित बीमारियों के रोकथाम जन जागरुकता हेतु प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी हनुमान प्रसाद नामदेव द्वारा बताया गया कि मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलती है, जिसमें ठण्ड देकर बुखार उल्टी, बेचैनी, सिर दर्द आदि लक्षण हो पायें जाते हैं। इसकी जांच समस्त शासकीय अस्पतालों, उप. स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम की आशा के पास जांच एवं उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। मच्छरों के काटने से बचने हेतु सोते समय मच्छरदानी अवश्य लगायें एवं अपने घर के आस-पास साफ-सफाई रखें, अनावश्यक पानी को जमा न होने देवें, ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सकें। इस अवसर पर जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, जिला व्ही-बी-डी-सलाहकार, जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर उपस्थित रहे।

जन कल्याण शिविरों में आवेदनों के निराकरण में नगर निकायों का बेहतर प्रदर्शन

शहडोल। जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे जन कल्याण शिविरों में प्राप्त 3035 आवेदनों में से 2325 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 4 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार कुल 2329 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा 706 प्रकरण लंबित हैं। जनपद पंचायत गोहपारू में प्राप्त 292 आवेदनों में से 29 आवेदन स्वीकृत तथा 1 आवेदन अस्वीकृत किया गया है। कुल 30 प्रकरणों का निराकरण होने के बाद 262 प्रकरण लंबित हैं। ब्यौहारी विकासखंड में 183 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5 आवेदन स्वीकृत कर उनका निराकरण किया गया है, जबकि 178 प्रकरण लंबित हैं। वहीं सोहागपुर-शहडोल विकासखंड में प्राप्त 121 आवेदनों का अभी निराकरण नहीं हो सका है।जयसिंहनगर जनपद पंचायत में 999 आवेदन प्राप्त हुए जो निराकरण हेतु लंबित हैं। बुढार विकासखंड में प्राप्त 188 आवेदनों में से 133 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और 55 आवेदन लंबित हैं। बकहो नगर परिषद में प्राप्त 75 आवेदनों में से 5 प्रकरणों का निराकरण किया गया है तथा 70 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार धनपुरी नगर पालिका में 40 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 22 प्रकरणों का निराकरण कर 18 प्रकरण लंबित हैं। बुढार नगर परिषद में प्राप्त 12 आवेदनों में से 10 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा 2 आवेदन लंबित हैं। शहडोल नगर पालिका में कुल 124 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 121 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 3 आवेदन अस्वीकृत किए गए। इस प्रकार यहां प्राप्त सभी 124 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। नगर परिषद ब्यौहारी में 1001 आवेदन प्राप्त हुए जो निराकरण हेतु लंबित हैं।

धूमधाम से मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव

जयसिंहनगर। शासन के निर्देशानुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदेला में मंगलवार 16 जून 2026को शाला प्रवेश उत्सव के अंतर्गत द्वितीय चरण का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा मंडल जयसिंहनगर रामनारायण पांडेयएवं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा मंडल करकी राजेश द्विवेदी तथा ग्राम पंचायत चंदेला सरपंच प्रतिनिधि दिलीप सिंह कंवर व अन्य जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया तथा बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया।

वन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस की भूमिका पर भी उठे गंभीर सवाल

जंगल के रखवालों पर लगातार हमले

शहडोल।

जिले में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की दरमियानी रात एक ही रात में वन अमले पर दो अलग-अलग हमलों ने न केवल वन कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि कानून-व्यवस्था और अवैध खनन माफियाओं के बढ़ते प्रभाव को भी उजागर कर दिया है। डिप्टी रेंजर की टीम पर हमला, डीएफओ के वाहन में तोडफ़ोड़ तथा दो वनकर्मियों के साथ मारपीट की घटनाओं ने यह संकेत दे दिया है कि जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले कर्मचारी खुद असुरक्षित हैं। घटनाक्रम के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और कथित संरक्षण को लेकर भी गंभीर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

एक रात, दो-दो हमले

जानकारी के अनुसार दक्षिण वन मंडल शहडोल को अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की सूचना मिली थी। इसके बाद वन विभाग की टीम रात्रिकालीन गश्त पर निकली। निपानिया-जरवाही मार्ग पर गश्त के दौरान डिप्टी रेंजर बरखेड़ा श्रीप्रसाद, डिप्टी रेंजर प्रकाश शुक्ला एवं अन्य अधिकारियों का वाहन अज्ञात लोगों के निशाने पर आ गया। आरोप है कि कुछ युवक लगातार वन विभाग की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और बाद में वाहन के सामने आकर हमला कर दिया। इस दौरान विभागीय वाहन में तोडफ़ोड़ की गई और हमलावर मौके से फरार हो गए।

वनकर्मियों को घसीटकर पीटा

पहली घटना के कुछ घंटे बाद बैजौरी क्षेत्र में दूसरी वारदात सामने आई। गश्त से लौट रहे बीट गार्ड सुरेश बैगा और रामकिशोर बैगा पर नरसरहा रोड स्थित डिपो और गणेश मंदिर के बीच अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। बताया गया कि बाइक सवार बदमाशों ने वनकर्मियों का रास्ता रोका, गला पकडक़र घसीटा और मारपीट की। हमले में दोनों कर्मचारियों को चोटें आईं। घायल कर्मचारियों को उपचार उपलब्ध कराया गया तथा पूरे घटनाक्रम की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई।

माफियाओं की निगरानी का आरोप

वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि गश्त के दौरान कुछ संदिग्ध युवक लगातार टीम की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। आरोप यह भी है कि सूचना देने के बावजूद मौके पर पहुंची डायल-112 से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। विभागीय सूत्रों का कहना है कि वन अमले को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, ताकि अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई प्रभावित हो सके।

रेत माफिया और बढ़ती बेखौफी

जिले में वर्तमान में रेत खदानों का नियमित ठेका नहीं होने के कारण अवैध उत्खनन और परिवहन के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्रतिदिन भारी मात्रा में रेत परिवहन की शिकायतें मिलती रही हैं। वन विभाग के कर्मचारियों पर बार-बार हो रहे हमले यह संकेत देते हैं कि अवैध कारोबार से जुड़े तत्व अब सरकारी अमले को सीधे चुनौती देने लगे हैं। इससे पहले भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ छीना-झपटी, वर्दी फाडऩे और शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल

घटना का एक चिंताजनक पहलू यह भी रहा कि बुधवार सुबह से वन विभाग के अधिकारी कोतवाली पहुंच गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होने में देर हुई। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा जैसी गंभीर घटनाओं के बावजूद तत्काल कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। यदि सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई नहीं होती, तो आम नागरिकों की शिकायतों की स्थिति क्या होगी, यह सहज ही समझा जा सकता है। जिले में लंबे समय से अवैध रेत कारोबार को लेकर पुलिस संरक्षण की चर्चाएं भी समय-समय पर सामने आती रही हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न

लगातार हो रहे हमलों ने वन विभाग के मैदानी अमले में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले कर्मचारियों को यदि सुरक्षा नहीं मिलेगी तो अवैध खनन, लकड़ी तस्करी और वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं होगा। प्रशासन और पुलिस के लिए यह घटना केवल मारपीट का मामला नहीं बल्कि कानून के शासन को खुली चुनौती के रूप में देखी जानी चाहिए।

वन अमले पर हमले के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन

सोहागपुर तहसील के ग्राम बिजौरी, नरवार और बगैहा क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण की शिकायतों के बाद खनिज और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। मुडन्ना नदी एवं आसपास के क्षेत्रों में करीब 520 घन मीटर अवैध रेत का भंडारण मिला, जिसे जेसीबी से मिट्टी मिलाकर नष्ट किया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में इसी क्षेत्र में वन विभाग के अमले पर हमला और तोडफ़ोड़ की घटना भी सामने आई थी। कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियां लंबे समय से संचालित थीं। विभाग ने निजी भूमि मालिकों के विरुद्ध सत्यापन उपरांत प्रकरण दर्ज करने की बात कही है।

इनका कहना है...

मामले की जांच एसडीओ स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। माफियाओं के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि मेरी गाड़ी में भी तोडफ़ोड़ की गई है। दोनों मामलों की शिकायत संबंधित थानों में की जा रही है।

श्रद्धा पेंद्रो
डीएफओ, दक्षिण वन मंडल शहडोल

दो वनकर्मियों के साथ मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

राघवेंद्र तिवारी कोतवाली प्रभारी, शहडोल

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना शासन की प्राथमिकता: कमिश्नर

जनकल्याण शिविर में नागरिकों के आवेदनों की ,की गई सुनवाई

शहडोल।

राज्य शासन के मंशानुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और विभागीय योजनाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम भाद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी ने शिविर में पहुंचे ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुना। आवेदकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मौके पर ही उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों को आवेदनों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।

शिविर को संबोधित करते हुए कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को शासकीय योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ मिले। आमजन को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला या ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, इसीलिए इस प्रकार के मैदानी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सचेत किया कि प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण ढंग से होना चाहिए, ताकि जनता का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत हो। कमिश्नर ने ग्रामीणों से भी आह्वान किया कि वे जागरूक बनें और विभागीय स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं की पात्रता समझकर उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

शिविर के दौरान शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों द्वारा विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विशेष विकासात्मक एवं हितग्राही मूलक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आजीविका मिशन, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि, सामाजिक न्याय और जनजाति कार्य विभाग शामिल रहे। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया।

इस जनकल्याण शिविर में ग्राम भाद सहित पोड़ी, आमाडांड, मलगा, चोड़ी, चुकानी, टांकी, बाडीखार, शिकारपुर, बरतराई, दारसागर जैसे अनेक आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं और मांगें लेकर उपस्थित हुए। शिविर में नामांकन, सीमांकन, आयुष्मान कार्ड बनाए जाने, जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने, आवास बनाए जाने संबंधी अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन ग्रामीणों से प्राप्त हुए। शिविर के दौरान कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को समय-सीमा में निराकरण हेतु सौंप दिया गया।

सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम: बुधपाल सिंह

यूसीसी लागू करने के संबंध में आमनागरिकों से आनलाईन सुझाव देने की कलेक्टर ने की अपील

शहडोल में यूसीसी पर मंथन, अंतिम ड्राफ्ट के लिए मांगे गए जनसुझाव

शहडोल।

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य शासन द्वारा प्रकिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट स्थित विराट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता, पत्रकार, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल रहे। यूसीसी समिति के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में निहित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक समानता, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने इसके ऐतिहासिक संदर्भों को रेखांकित करते हुए बताया कि गोवा में यह व्यवस्था आजादी के पूर्व से ही प्रभावी रूप से लागू है। वर्तमान में उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के बाद मध्यप्रदेश भी इसे लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसा करने वाला यह देश का चौथा राज्य होगा।वर्तमान कानूनी विसंगतियों पर चर्चा करते हुए श्री बुधपाल सिंह ने बताया कि अभी विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण (गोद लेना) और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के अधीन आते हैं। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य इन सभी विषयों पर एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं को समाज में पुरुषों के समकक्ष समान अधिकार मिल सकें। संहिता के लागू होने से विवाह का अनिवार्य पंजीकरण होगा, बेटे-बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, गोद लेने की प्रक्रिया पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होगी और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। बैठक में यूसीसी के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य श्री बुधपाल सिंह ने संहिता के प्रावधानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों से संहिता को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए सुझाव एवं विचार प्राप्त किए गए। विधायक जैतपुर विधानसभा क्षेत्र जयसिंह मरावी ने कहा कि प्रदेश में एक प्रधान, एक निसान और एक विधान लागू होना चाहिए। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने पॉवर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए जिले के आम नागरिकों से ऑनलाईन सुझाव देने के अपील की। उन्होने बताया कि ीजजचेरूध्ध्नबबण्उचण्हवअण्पद पर ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, सुदीप शुक्ला, डॉ. मिश्रा, अधिवक्ता रमेश त्रिपाठी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश सिंह, अधिवक्ता रवीन्द्र श्रीवास्तव, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कल्याण वाजपेयी, सदस्य पूर्णिमा बैनर्जी, प्रीती राय, पत्रकार रविन्दर सिंह गिल, विष्णुप्रताप सिंह सहित अन्य सदस्यों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। वक्ताओं ने विशेष रूप से विवाह की आयु, भरण-पोषण की राशि और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमन के लिए बनाए जाने वाले प्रावधानों में पूर्ण स्पष्टता रखने पर जोर दिया। इसके साथ ही, आमजन तक इस कानून की सही जानकारी पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव भी दिया गया ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम या अफवाहों को फैलने से रोका जा सके।बैठक में जनपद अध्यक्ष श्रीमती हीरावती कोल, नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, श्रीमती मिनिषा पाण्डेय, डॉ. राजेश पाण्डेय, पार्षद, जनपद पंचायतों के जनपद सदस्य, अभिषेक चौकसे, रवीन्द्र श्रीवास्तव सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, एनजीओ, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनन्द राय सिन्हा, जिला योजना अधिकारी श्री अहिरवार, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

किसानों को दिलाएं योजनाओं का लाभ, कोई भी पात्र किसान न रहे वंचित: कमिश्नर कमिश्नर ने दारसागर क्लस्टर का किया निरीक्षण, किसानों से किया संवाद

शहडोल।

कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने आज अनूपपुर जनपद के दारसागर क्लस्टर का निरीक्षण कर क्षेत्र में संचालित कृषि एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न कृषि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन करते हुए मैदानी व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा किसानों से संवाद कर योजनाओं के लाभ और उनकी प्रभावशीलता की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने उन्नत कृषि पद्धतियों, आधुनिक सिंचाई तकनीकों तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अवलोकन किया। उन्होंने कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले को निर्देश दिए कि किसानों के बीच नियमित रूप से पहुंचकर उन्हें नवीन कृषि तकनीकों और शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

कृषकों से चर्चा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता किसानों की लागत कम कर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ फसल विविधीकरण अपनाने, श्रीअन्न (मोटे अनाज) के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा जल संरक्षण के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियों का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग से कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। किसानों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए तथा विभिन्न योजनाओं से प्राप्त लाभों के अनुभव बताए। किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कमिश्नर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी- कर्मचारी, प्रगतिशील कृषक एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

सीएचसी मानपुर में अंगद बने बाबू और वार्ड बॉय

मानपुर। लगता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में सरकारी नियमों का नहीं, बल्कि अंगद के पैर का कानून चलता है। शासकीय गाइडलाइन कहती है कि हर तीन से चार साल में कर्मचारियों की गोटियां बदलनी चाहिए, यानी ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन मानपुर अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर वार्ड बॉय तक, यहां ऐसी फेविकोल की गोंद लगाकर बैठे हैं कि ट्रांसफर की हर गाइडलाइन इनके रसूख के आगे घुटने टेक देती है। वर्षों से एक ही मसनद पर जमे इन चिरस्थायी नुमाइंदों के चलते अस्पताल की व्यवस्थाएं अब इनके पर्सनल वीआईपी चेंबर जैसी लगने लगी हैं। ग्रामीण इलाज के लिए भटक रहे हैं और ये मानपुर को अपनी जागीर समझकर हुकूमत चला रहे हैं। आखिर इन साहबों पर इतनी मेहरबानी क्यों, क्या इनका ट्रांसफर करने से जिले का स्वास्थ्य महकमा बीमार हो जाएगा, अब परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ला से गुहार लगाई है। मांग सीधी है कि इन अंगद के पैरों को तत्काल उखाड़ा जाए, इनका फेरबदल कर अन्यत्र भेजा जाए और नई खेप लाई जाए, ताकि मानपुर के गरीबों को इलाज नसीब हो सके।

फांसी लगाकर दो व्यक्तियों ने की खुदकुशी

कटनी। विजयराघवगढ़ एवं रीठी थाना क्षेत्र में दो व्यक्तियों द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी किये जाने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार रीठी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम टोला गोदाना में 55 वर्षीय शिवचरण लोधी ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना कर मर्ग कायम किया है। इसी तरह विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया पहरहाई में 26 वर्षीय दस्सी कोल ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी।

जहरीले पदार्थ के सेवन से युवक की मौत

कटनी। कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गल्ला मंडी निवासी 27 वर्षीय नीरज चौधरी पिता सोमनाथ चौधरी ने सोमवार दोपहर करीब 2:54 बजे किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे मंडी पहरूआ स्थित शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल के वार्डब्वॉय वीरेंद्र समुदे की सूचना पर कुठला पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है।

सचिव और जीआरएस को शोकाज नोटिस जारी

सिलौंडी। ढीमरखेड़ा के मंगल भवन में बड़वारा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह , कलेक्टर आशीष तिवारी, एसपी अभिनय विश्वकर्मा जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता संतोष दुबे ,मंडल अध्यक्ष अजय सोनी , मनीष सिंह बागरी,नरेंद्र त्रिपाठी से क्षेत्र के जन प्रतिनिधि की मौजूदगी शिविर में बहुत ही कम संख्या में कुल 70 आवेदन जमा हुए जबकि 72 ग्राम पंचायत होने से हर पंचायत से 2 या 3 आवेदन होने पर संख्या 200 से की चाहिए था ।

भोपाल से दिल्ली तक फाइल मैनेजमेंट का अचूक नुस्खा

वाह साहब! बाघों की मज़ार पर पर्यटन का जश्न

रईसों की रील में कैद जंगल का राजा, अवार्ड पाकर गदगद साहब

उमरिया। बधाई हो साहब! बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2026 में देश के सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव पर्यटन स्थल का तमगा मिला है। भोपाल से दिल्ली तक पीठ थपथपाई जा रही है, मिठाइयां बंट रही हैं और साहबों के चेहरों पर वो चमक है जो शायद खुद बाघ के बदन पर भी न हो, लेकिन इस चमचमाती ट्रॉफी की आड़ में जो सच छुपाया जा रहा है, उसकी सड़ांध अब जंगल से बाहर आने लगी है। सवाल सीधा है कि क्या इस सरकारी पाउडर-क्रीम से बांधवगढ़ के चेहरे पर लगे बाघों के खून के दाग धुल जाएंगे। जंगल के भीतर का सच यह है कि नेशनल पार्क अब वन्यजीवों का आशियाना कम और रईसजादों का पिकनिक स्पॉट ज्यादा बन चुका है।

बाघों को बंधक बनाती जिप्सी ब्रिगेड

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की किताबें शायद दफ्तरों की अलमारियों में दीमक चाट रही हैं। कानून कहता है कि वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में निर्बाध जीवन जीने का हक है, लेकिन बांधवगढ़ में नियम कायदे सिर्फ कागजों पर दहाड़ते हैं, जमीन पर तो साहब और सैलानी दहाड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो इस बात की गवाह हैं कि कैसे एक बाघ को देखकर 20-25 जिप्सियां उसे इस तरह घेर लेती हैं जैसे वह जंगल का राजा नहीं, बल्कि किसी सस्ते सर्कस का बंधक कलाकार हो। पर्यटकों की चीख-पुकार, मोबाइल कैमरों की फ्लैशलाइट और वाहनों का धुंआ। बाघों के पीछे दौड़ती गाडिय़ां और रसूखदारों के लिए कायदे-कानूनों की धज्जियां उड़ाना। वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार में इस कदर दखल कि जानवर अब खुद डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। अगर बाघों को डराकर, उन्हें घेरकर रईसों का मनोरंजन करना ही पर्यटन है, तो फिर चिडिय़ाघर और बांधवगढ़ में फर्क ही क्या रह गया।

भोपाल से दिल्ली तक मैनेजमेंट का खेल

पुरस्कारों की चमक के पीछे उन बेजुबानों की चीखें दबा दी गईं जो पिछले कुछ सालों में रहस्यमयी तरीके से मौत के मुंह में सो गए। बांधवगढ़ में बाघों की लगातार होती मौतों पर जब-जब सवाल उठे, प्रबंधन ने जांच की ऐसी लोरी सुनाई कि मामला ठंडे बस्ते में सो गया। जानकारों की मानें तो बाघों की मौतों और शिकार की आशंकाओं से जुड़ी कई संवेदनशील फाइलें भोपाल से लेकर दिल्ली तक के दफ्तरों में धूल खा रही हैं। जांचें चल रही हैं, कमेटियां बन रही हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही है। विरोधी और वन्यजीव प्रेमी पूछ रहे हैं कि जब जमीनी हकीकत इतनी खौफनाक है, जब संरक्षण के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है, तो फिर यह राष्ट्रीय सम्मान किस आधार पर थमा दिया गया?

हेरिटेज या नोट छापने की मशीन

प्रबंधन के लिए बाघ शायद अब देश की अमूल्य धरोहर नहीं, बल्कि नोट छापने की मशीन बन चुका है। वीआईपी कल्चर ने पूरे रिजर्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अनुशासनहीनता की हद पार हो चुकी है। कैमरे चमकाकर रील बनाने वाले हुड़दंगियों को खुली छूट है, क्योंकि वे मोटी रकम जो देकर आते हैं। अगर संरक्षण ही पहली प्राथमिकता होती, तो बार-बार नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने न आतीं। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में मौन सहमति दे दे, तो जंगल को भगवान भरोसे ही माना जाएगा। पुरस्कारों की गूंज में उन स्थानीय गाइडों और वनकर्मियों की आवाज दबा दी गई जो रोज इस अव्यवस्था को देखकर खून के घूंट पीते हैं।

संरक्षण के लिए नहीं मिला है सम्मान

बांधवगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान मिलना गर्व की बात जरूर हो सकती है, लेकिन याद रहे कि यह सम्मान टूरिज्म को मिला है, कंजर्वेशन (संरक्षण) को नहीं। अगर सैलानियों की आवभगत के चक्कर में बाघ ही नहीं बचेंगे, तो कल यह ट्रॉफी किसे दिखाओगे, अब वक्त आ गया है कि प्रबंधन अपनी पीठ थपथपाना बंद करे और इन तीखे सवालों का सामना करे। जनता की नजरें टिकी हैं कि स्पष्टीकरण दीजिए, वरना इतिहास आपको जंगल का रक्षक नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी का मूकदर्शक लिखेगा।

जनपद एपीओ और उपयंत्री की भूमिका संदिग्ध

15 लाख का चेकडैम चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट

मानपुर। जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत छपडौर में विकास के नाम पर सरकारी राशि का खुलेआम बंदरबांट करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। धखोदर रोड स्थित नउवा ढोढ नदी पर 15वें वित्त आयोग की राशि से बने एक चेकडैम ने धरातल पर आने से पहले ही दम तोड़ दिया है। 15 लाख रुपये की भारी-भरकम लागत से बने इस चेकडैम में न तो क्रॉस बैरियर है और न ही रिटर्न वॉल। घटिया निर्माण और चोरी की रेत के दम पर खड़े किए गए इस ढांचे ने जनपद पंचायत के तकनीकी अधिकारियों और जिम्मेदार प्रशासनिक अमले की पोल खोलकर रख दी है।

आधे पैसों में समेटा काम

नियमों के मुताबिक, किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत में ही एजेंसी का विवरण, लागत और तकनीकी जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है। लेकिन छपडौर पंचायत में आज तक कोई सूचना पटल नहीं लगाया गया। सूत्रों की मानें तो महज आधे बजट में औपचारिकता पूरी कर बाकी की मोटी रकम ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत के आला अधिकारियों की जेबों में सरका दी गई है। जनता के टैक्स के पैसे पर इस तरह डाका डालना बिना किसी बड़े वरदहस्त के संभव नहीं है।

पर्दे के पीछे से सरपंच पति चला रहे सरकार!

इस पूरे खेल में सबसे मजेदार पहलू यह है कि ग्राम पंचायत छपडौर में महिला सशक्तिकरण का मखौल उड़ाते हुए सरपंच पति संमपत कोरी खुद को अघोषित सरपंच मानकर फैसले ले रहे हैं। जब उनसे इस महाघोटाले पर जवाब मांगा गया, तो उन्होंने हमेशा की तरह घिसे-पिटे अंदाज में खुद को दूध का धुला बताते हुए कहा कि काम स्टीमेट के हिसाब से साफ-सुथरा हुआ है। वहीं पंचायत के सचिव अयोध्या राय इस कदर लापरवाह हैं कि उन्हें अपनी ही पंचायत में चल रही किसी जांच या गड़बड़ी की कोई सुध तक नहीं है।

जांच के नाम पर एपीओ का गोलमोल खेल

इस भ्रष्टाचार की कहानी में सबसे बड़े खिलाड़ी जनपद पंचायत की तकनीकी और प्रशासनिक टीम नजर आ रही है। मामले को लेकर जब जनपद पंचायत के एपीओ से बात की गई, तो उन्होंने 15 दिन पहले ही सीना ठोककर दावा किया था कि जांच दल गठित कर दिया गया है। अगर जांच टीम गठित हो चुकी है, तो उसमें कौन-कौन शामिल है, जांच कब तक पूरी होगी, इन सवालों पर एपीओ साहब की बोलती बंद क्यों हो जाती है?जब भी मीडिया या जागरूक नागरिकों द्वारा जांच आदेश की कॉपी मांगी जाती है, तो एपीओ साहब गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। जांच के नाम पर महीनों से चल रही यह ढुलमुल नीति साफ इशारा करती है कि इस घोटाले के तार सीधे जनपद एपीओ और संबंधित उपयंत्री से जुड़े हुए हैं। बिना उपयंत्री के मूल्यांकन और एपीओ की मूक सहमति के, 15 लाख रुपये की फाइल को इस तरह ठिकाने नहीं लगाया जा सकता था। इन दोनों अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका अब सीधे तौर पर जांच के दायरे में है।

कलेक्टर और सीईओ से निष्पक्ष जांच की आस

इस खुलेआम लूट के बाद अब कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय और जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया से क्षेत्र की जनता को भारी उम्मीदें हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे जनपद एपीओ और उपयंत्री के खिलाफ तत्काल कड़ा रुख अपनाया जाए। एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच टीम गठित कर इस घोटाले की परतें खोली जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और सरकारी पैसे को अपनी जागीर समझने वाले इन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

इनका कहना है

अभी जनपद पंचायत में शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे खाली होंगे देखते हैं ।
राजेश जाटव
एपीओ
जनपद पंचायत मानपुर

सड़क में जगह-जगह हो गये गड्ढे, चलना हुआ मुश्किल

कोतमा। बस स्टैंड से जकीरा चौक तक जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर हो गई है सड़क में जगह-जगह दो दर्जन से ज्यादा गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण आमजन को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। कई बार नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन के साथ ही नपा अध्यक्ष अजय सराफ से जर्जर सड़क की मरम्मत करवाये जाने को लेकर शिकायत भी की लेकिन नगर पालिका के द्वारा यह कहा जाता है कि सड़क की जांच चल रही है जांच पूरी होने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। जबकि इस सड़क का निर्माण पूर्व परिषद के कार्यकाल में वर्ष 2019 में करवाया गया था लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण यह सड़क बनते ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पूर्व परिषद के द्वारा वर्ष 2019 में नगर पालिका निधि से लगभग 27 लाख की लागत से बस स्टैंड से जकीरा चौक तक ठेकेदार के माध्यम से सीसी सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया था। और यह सड़क बनते ही उखड़ने लगी थी जिस पर नागरिकों ने आपत्ति जताई तो ठेकेदार ने रातों-रात सीसी सड़क के ऊपर डामरीकारण करते हुए सड़क का निर्माण कार्य कर दिया लेकिन वह सड़क भी ज्यादा दिन नहीं चली और बनते ही सड़क में जगह-जगह गड्ढे हो गए सड़क पूरी तरह से उखड़ गई।

मंत्री का निर्देश बेअसर

मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को दो साल पूर्व नगर पालिका सभाकक्ष में बैठक के दौरान लोगों ने शिकायत भी सड़क की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्य को लेकर की थी जिस पर मंत्री ने तत्काल ही नगरीय प्रशासन विभाग शहडोल से बात की थी और उन्हें सड़क का निर्माण कार्य करवाए जाने के निर्देश दिए थे लेकिन उसके बाद भी सड़क का निर्माण कार्य दोबारा से नहीं करवाया जा रहा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मंत्री के निर्देश पर अमल नही किया गया। बस स्टैंड से जकीरा चौक तक जाने वाली सड़क में जगह-जगह गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दो पहिया वाहन चालकों को सड़क में गड्ढे नजर ही नहीं आती हैं। जिसके कारण वाहन चालकों को हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। आये दिन पैदल चलने वाले राहगीर सड़क पर गड्ढे होने के कारण गिर कर चोटिल हो रहे हैं। पूर्व परिषद के द्वारा सड़क की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार का भुगतान भी रोक दिया गया था वर्तमान में भी सड़क निर्माण की जांच होने के कारण नगर पालिका के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ठेकेदार को अभी भुगतान नहीं किया गया है। लेकिन अंदर की बात क्या है यह नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ठेकेदार की कमियो का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। दुकानदार धीरू अग्रवाल का कहना है कि बस स्टैंड से जकीरा चौक तक जाने वाली सड़क बहुत ही खराब हो गई है सड़क की गुणवत्ता को लेकर निर्माण समय से ही सही काम सही नहीं था बारिश के बाद सड़क की और खराब स्थिति हो गई है जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण पैदल चलने में परेशानी होती है आए दिन राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सड़क मे दो दर्जन से ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। बरसात पे बरसात बीत रही है और आश्वासन ही मात्र मिल रहा है सड़क का मरम्मत कार्य अभी तक नही करवाया गया।

इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार श्याम सोनी का कहना है हमारे दुकान के सामने से निकलने वाली सड़क की दयनीय स्थिति हो गई है पता ही नही चलता है सड़क मे गड्ढे हैं या गड्ढों मे सड़क है। नगर पालिका के द्वारा बारिश के बाद सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने की बात कही गई थी लेकिन साल बीत गया और फिर से बरसात का मौसम शुरू होने वाला है अभी तक निर्माण कार्य शुरू तक नही किया गया। सड़क मे गड्ढे होने के कारण लोगों को सड़क ढूंढकर चलना पड़ता है नगर पालिका के द्वारा डस्ट डलवाया गया था जो पिछले बारिश के साथ ही बह गई। प्रतिदिन राहगीर एवं वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गांव से भी बद्तर स्थिति इस सड़क की हो गई है। ठेकेदार की खामियाजा का नतीजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। नगर पालिका के द्वारा जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य करवाने की मांग की है।

इनका कहना है

नागरिकों की परेशानी को देखते हुए जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया जायेगा।
अजय सराफ, अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद कोतमा

नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में जन कल्याण शिविर आयोजित

राजनगर। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में मध्यप्रदेश शासन के (आयुक्त) नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल के निर्देश तथा कलेक्टर अनूपपुर के आदेश पर नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में बुधवार को लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक सीधे आम जनता और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना था। इस शिविर के पंजीयन केंद्र व सहायता केंद्र के उपस्थित कर्मचारियों के माध्यम से हितग्राहियों की सहायता की गई। इस लोक कल्याण शिविर में 22 से अधिक विभागों ने लगाए शिविर। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास कि लोकप्रिय लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्पॉन्सरशिप शालापूर्व शिक्षा योजना, कल्याणी पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, कृषि, श्रम, राजस्व, खाद्यान्न पर्ची, आधार सुधार योजना सहित अनेक विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। इन विभागों के कर्मचारीयो ने मौके पर ही आमजन को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का नाम जैसे- प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पेंशन योजनाएं की विस्तृत जानकारी दी। तथा उनके आवेदन पत्र लिए।

पात्र हितग्राहियों को मिलेंगे स्वीकृति पत्र-मुख्य नपा अधिकारी

नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में जनकल्याण शिविर को लेकर विगत तीन दिन पूर्व लखन लाल पनिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पोस्टर, बैनर के माध्यम से शासन की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कराया जा रहा था। साथ ही वाहनों के माध्यम से नगर के प्रमुख स्थानो तथा वार्डों में मुनादी/अनाउंसमेंट करवा रहे थे। कार्यक्रम के दिन भी नगर में वाहनों से मुनादी/अनाउंसमेंट हो रहा था। हितग्राहियों को जानकारी मिलते ही वे अधिक से अधिक संख्या में नगर परिषद कार्यालय प्रांगण के शिविर में पहुंचकर इस योजना का लाभ ले रहे थे। जिससे सैकड़ो हितग्राहियों को मिली राहत। इस शिविर का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि नगरवासियों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े।

एक ही छत के नीचे कई समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण

नगर परिषद बनगवां (राजनगर) क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष धनंजय सिंह, सुरेश गौतम, धर्मेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, वरिष्ठ भाजपा नेता सच्चिदानंद सिंह, वार्ड पार्षद समय पटेल, मनोज चंदेल, गिरजा विश्वकर्मा, मनोज सिंह विधानसभा मीडिया प्रभारी भाजपा, पंकज कुमार शर्मा भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी, पार्षद पति जितेंद्र पनिका, संतोष जायसवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और कार्यकर्ता एवं नगर के सम्मानिय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी उपस्थित रहे जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम का कवरेज किया। शासन द्वारा चलाए गए सभी विकाश कार्यों को सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। शासन द्वारा सभी विकास कार्यों को सीधे जनता तक पहुंचाना ही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रहा।

शिविर में पधारे हितग्राहियों के लिए विशेष व्यवस्था

नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में मध्यप्रदेश शासन की लोक कल्याण शिविर में पधारे हितग्राहियों के लिए शीतल पेयजल, चाय, स्वल्पाहार, बैठने हेतु कुर्सी तथा धूप से बचाव हेतु टेन्ट तथा कुलर की व्यवस्था उपलब्ध रही। लखन लाल पनिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वयं शिविर कि नियमित मॉनिटरिंग कि जा रहा थी। समय-समय पर माइक के माध्यम से विशेष जानकारी प्रदान की जा रही थी। हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो जिसके लिए पंजीयन

हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

केंद्र तथा सहायता केंद्र के कर्मचारियों द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा था। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) द्वारा आज शासन द्वारा चलाए गए। सभी योजनाओं को सीधे जनता के पास एक ही जगह से सभी योजनाओं का लाभ बताकर पात्र हितग्राहियों को उसका लाभ दिलवाया गया।

सीएम हेल्पलाइन सहित कई शिकायतों का मौके पर हुआ निराकरण

इस शिविर में विशेष रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी लखनलाल पनिका द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कई लंबित प्रकरणों में हितग्राहियों की समस्याओं को स्वयं सुना तथा उनकी शिकायतों का त्वरित परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की। शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया गया। जिससे नागरिकों को त्वरित राहत मिली और प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ।

खबर संक्षेप

अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, आरोपी गिरफ्तार

बुढ़ार। जिले में अवैध उत्खनन और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुढ़ार थाना पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर अवैध रेत से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहन और रेत की कुल कीमत करीब 5.50 लाख रुपये आंकी गई है।जानकारी के अनुसार, 17 जून 2026 को बुढ़ार थाना पुलिस की टीम क्षेत्र में भ्रमण पर थी। इसी दौरान मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि जमुनिहा नाला (लालपुर) से एक बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर, उसे बेचने के लिए बुढ़ार की ओर ले जा रहा है।सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और लालपुर हवाई पट्टी के पास पीपरतरा तिराहा (मेन रोड) पर घेराबंदी कर दी। कुछ ही देर में संदिग्ध ट्रैक्टर आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोककर उसकी जांच की। पुलिस की पूछताछ में ट्रैक्टर चालक ने सुनील कोल (पिताः नाथन कोल, उम्रः 32 वर्ष), निवासी ग्राम लालपुर, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल बताया। जब पुलिस ने चालक से रेत के परिवहन और वाहन से संबंधित वैध दस्तावेज (रॉयल्टी आदि) मांगे, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। जब्त मशरूकाः बिना नंबर का ट्रैक्टर और रेत से भरी ट्रॉली (कुल अनुमानित कीमत □5,50,000/-)आरोपीः सुनील कोल (उम्र 32 वर्ष), निवासी लालपुर। भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत मामला दर्ज। मौके पर ही अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया और सुरक्षा के लिहाज से बुढ़ार थाने में खड़ा करवाया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक चेतराम कौशिक और आरक्षक गोपाल सिंह की मुख्य व सराहनीय भूमिका रही।

आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी

उमरियापान। आशा ऊषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं का पिछले तीन माह से लंबित भुगतान शीघ्र कराने की मांग उठाई है। भुगतान की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने उमरियापान में मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस संबंध में संगठन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले तीन माह से आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं को मानदेय और अन्य देयकों का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान लंबित रहने से कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्हें परिवार के भरण-पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसके बावजूद समय पर भुगतान नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपेंगी।

सीईओ ने पंचायत सचिवों को किया इधर उधर

उमरियापान। जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने जिले की 44 ग्राम पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों को इधर से उधर भेजा है। इसी क्रम में ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत की मंगेली ग्राम पंचायत में पदस्थ पंचायत सचिव मनीष रंजन मिश्रा का ग्राम पंचायत पोंडी खुर्द तबादला किया है। ठिर्री में पदस्थ सुशील बर्मन की गोपालपुर जबकि पिपरिया सहलावन ग्राम पंचायत के सचिव अनिल दीक्षित को बहोरीबंद के ग्राम पंचायत भरदा बड़खेरा भेजा है। देवरी मंगेला सचिव उत्तम चंद पटेल को बहोरीबंद की छपरा पंचायत और खाम्हा पंचायत सचिव दीनू साहू को बहोरीबंद के सलैया कुआं में पदस्थ किया है। इसके अलावा बहोरीबंद की छपरा पंचायत के सचिव विजय कोरी को ढीमरखेड़ा की पिपरिया सहलावन जबकि रीठी जनपद की घुड़हर ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव सुरेंद्र हल्दकार को भूला और रीठी जनपद की बरयापुर पंचायत में पदस्थ सोमनाथ पटेल को ढीमरखेड़ा की महगवां बड़खेरा पंचायत में पदस्थ किया है।

बुढार पुलिस की बड़ी कार्रवाईः अवैध वसूली, मारपीट और वाटर पार्क में चोरी के मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार

बुढार। अवैध वसूली, मार-पीट एवं वाटर पार्क में चोरी के दो मामलों में पुलिस ने 2 आरोपियों को अनुविभागीय पुलिस अधिकारी विकास पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बुढार विनय सिंह गहरवार के निर्देश पर स्थानीय पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

रास्ते में रोककर शराब के लिए अवैध वसूली और मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

17 जून 2026 की रात करीब 2 बजे फरियादी संतोष नामदेव (पिता गणेश नामदेव, उम्र 57 साल, निवासी वार्ड नं. 05, पुरानी बस्ती, बुढार) ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में आरोपी आयुष सिंह उर्फ बावला मिला, जिसने उसका रास्ता रोक लिया। आरोपी ने फरियादी से कहा, ₹तुम बहुत पैसा कमाते हो, मुझे खाने-पीने और शराब के लिए पैसे दो।₹ जब फरियादी ने अवैध रूप से पैसे देने से मना किया, तो आरोपी ने हाथ-मुक्के से उसकी बेरहमी से मारपीट की, जिससे फरियादी को कई जगह चोटें आईं। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।पुलिस कार्रवाईः फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्र. 429/26, धारा 126(2), 119(1), 296(ए), 115(2), 351(3) बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने तत्परता से आरोपी की तलाश कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

वाटर पार्क में चोरी का फरार सह-आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में

इससे पहले, बीते 25 मई 2026 को फरियादी गोरेलाल बैगा (पिता चनद्रिका प्रसाद बैगा, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम खाडा, जैतपुर) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह वाटर पार्क में सुपरवाइजरी का काम करता है। 24 मई 2026 की रात करीब 01:20 बजे वाटर पार्क परिसर में निर्माण कार्य के लिए रखी लोहे की रॉड और छल्ले चोरी कर एक व्यक्ति भाग रहा था। जब चौकीदार और स्टाफ ने उसे दौड़ाया, तो उसने चाकू दिखा कर डराने का प्रयास किया। हालांकि, स्टाफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी अंकित चौधरी को मोटरसाइकिल, चाकू और करीब 6, हजार रुपये कीमत के चोरी के छल्लों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस मामले में अपराध क्र. 370/26 धारा 308 बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी अंकित चौधरी को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन उसका साथी आरोपी राजेन्द्र सोनकर (निवासी अम्बेडकर नगर) घटना के दिन से ही फरार चल रहा था।पुलिस कार्रवाईः फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार के द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना और कड़े प्रयासों के बाद सह-आरोपी राजेन्द्र सोनकर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इन दोनों ही मामलों में सउनि ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रआर. शरद, प्रजापति, प्रधान आर.दशरथ, म.प्रआर. बसंता, प्रआर. जान सिंह और आर.कृष्णा की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।

शहडोल-अनूपपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसाः मेटाडोर और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर

बुढार। शहडोल एनएच 78 हाईवे पर बुधवार की दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बुढार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रा क्रेशर के समीप एक तेज रफ्तार मेटाडोर और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

लापरवाही बनी हादसे की वजह

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक मेटाडोर (वाहन क्रमांक MP 65 GA 1956) अनूपपुर से शहडोल की ओर जा रही थी। तभी मिश्रा क्रेशर के पास अज्ञात मेटाडोर चालक ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल (क्रमांक MP 18 MO) को जोरदार टक्कर मार दी।

एक की मौत, घायल जिला अस्पताल रेफर

टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पर सवार दो युवकों में से एक अज्ञात युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बुढार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए जिला चिकित्सालय शहडोल रेफर किया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है,बुढार पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और अज्ञात मेटाडोर चालक के खिलाफ सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

शहडोल में विद्युत कैरम प्रतियोगिता का शानदार आगाज

मुख्य अतिथि कलेक्टर ने किया शुभारंभ, 8 टीमों के बीच मुकाबला शुरू

शहडोल। जिला महिला समिति के प्रांगण में खेल और उत्साह का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (जबलपुर) के नेतृत्व में '48वीं अंतर क्षेत्रीय विद्युत कैरम क्रीडा प्रतियोगिता (वर्ष 2026-27)' का भव्य शुभारंभ हो गया है। मुख्य अभियंता शहडोल क्षेत्र के निर्देशन एवं अधीक्षण अभियंता जे. एस. नंदा के विशेष मार्गदर्शन में आयोजित यह तीन दिवसीय खेल उत्सव 19 जून 2026 तक चलेगा।

मां सरस्वती के पूजन से हुआ भव्य शुभारंभ

कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉ. केदार सिंह द्वारा विद्यादायिनी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर खेल भावना को सर्वोपरि रखने के लिए सभी उपस्थित खिलाडिय़ों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से खेल शपथ ग्रहण की। इसके तुरंत बाद, पहले दिन की प्रतियोगिता का बिगुल फूंकते हुए 8 दमदार टीमों के बीच कड़े और रोमांचक मुकाबलों की शुरुआत हुई। इस खेल महाकुंभ में मध्य प्रदेश के कोने-कोने से विद्युत विभाग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। प्रतियोगिता में शहडोल क्षेत्र, सिरमौर और बिरसिंहपुर पाली, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल क्षेत्र, सागर, उज्जैन, खंडवा और चचाई क्षेत्र की टीमें पूरे दमखम के साथ हिस्सा ले रही हैं।

आला अधिकारियों की रही गरिमामयी मौजूदगी

इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विभाग के शीर्ष अधिकारी बतौर अतिथि और आयोजन समिति के सदस्य के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता (शहडोल क्षेत्र) व संरक्षक प्रमिल कुमार मिश्रा, विशिष्ट अतिथि मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) श्री आदित्य कुमार परते, और अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) व अध्यक्ष श्री जे. एस. नंदा का मार्गदर्शन सराहनीय रहा। इसके साथ ही, आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने में कार्यपालन अभियंता व सचिव संजय वर्मा, कार्यपालन अभियंता श्री जितेंद्र कुमार, क्षेत्रीय लेखा अधिकारी अभिषेक देवांगन और प्रबंधक (मानव संसाधन) नागेश कुमार प्रजापति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तीन दिनों तक चलने वाले इस दिमागी और फुर्ती के खेल में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ष कैरम प्रतियोगिता की चमचमाती ट्रॉफी किस क्षेत्र के नाम होती है।

विधायक मनीषा सिंह ने किया चंदेला ग्राम का दौरा

जयसिंहनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा सिंह ने ग्राम पंचायत चंदेला का दौरा किया। इस दौरान विधायक श्रीमती मनीषा सिंह ने ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन सहित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों को

समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

विधायक श्रीमती सिंह ने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणजनों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं एवं मांगों को सुना। उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया तथा शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ग्रामीणों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।

उक्त अवसर पर भाजपा शहडोल जिला मंत्री श्रीमती कविता सिंह, भारतीय जनता पार्टी मंडल जयसिंहनगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती जयश्री कचेर, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम नारायण पाण्डेय, जनपद सदस्य शिवानी जायसवाल, सरपंच ग्राम पंचायत चंदेला दुर्गा देवी सिंह कंवर, पूर्व सरपंच दिलीप जायसवाल मंडल महामंत्री अनुपम द्विवेदी जी, मंडल महामंत्री हिमांशु गुप्ता,मंडल उपाध्यक्ष हीरालाल पाल, मंडल उपाध्यक्ष उमेश गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष अनूप मिश्रा, मंडल मंत्री श्रीमती मीना पाण्डेय, महिला मोर्चा मंडल महामंत्री श्रीमती शीला तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी राजेंद्र शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शेषमणि पाल, बूथ अध्यक्ष चंदेला मोहन कहार, बूथ बीएलए शिवाकांत पाण्डेय, श्रीमती मंजुला सिंह, अजय जायसवाल सहित बड़ी संख्या मे ग्राम निवासी उपस्थित रहे।

बुजुर्ग पेंशनर्स की टूटती सांसें और सरकार की बेरुखीः 20 साल का इंतजार, 59 महीने का एरियर्स अब भी बकाया

बुढार। मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स आज जीवन के उत्तरार्ध में सरकार की अनदेखी और अपने ही हक के पैसों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। 'सेवा निवृत्ति पेंशनर की व्यथा' आज सूबे में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। छठे और सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान न होने से नाराज और लाचार हो चुके वयोवृद्ध पेंशनर्स अब मुख्यमंत्री से 'संजीवनी' रूपी न्याय की गुहार सेवा निवृत्त शिक्षक पेंशनर रोहणी प्रसाद गर्ग लगा रहे हैं। 20 साल बीते, नहीं मिला 59 महीने का हक पेंशनर्स एसोसिएशन के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2006 से छठा वेतनमान लागू किया था, जिसका भुगतान सितंबर 2008 से शुरू हुआ। आज इस बात को 20 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन साल 2003, 2004, 2005 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स को 32 महीने का छठा वेतनमान एरियर्स आज तक नहीं मिला। इसी तरह, सातवें वेतनमान का 27 महीने का एरियर्स भी सरकार दबाए बैठी है। कुल मिलाकर 59 महीनों का एरियर्स आज भी बकाया है।

धारा 49(6) का बहाना और 'डबल इंजन' का विरोधाभास

बुजुर्गों का आरोप है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में एक ही दल की 'डबल इंजन' सरकार होने के बावजूद पेंशनर्स को सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। एरियर्स भुगतान के रास्ते में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को रोड़ा बनाया जा रहा है। दोनों राज्य सरकारें इस धारा को विलोपित (हटाने) करने के बजाय, इसी के सहारे एक-दूसरे पर दोषारोपण कर मामले को टाल रही हैं। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार की मंशा ही भुगतान की नहीं है, अन्यथा 20 साल का लंबा वक्त कम नहीं होता।

हाईकोर्ट से जीते, पर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में सरकार!

न्याय की उम्मीद में पेंशनर्स एसोसिएशन ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। कोर्ट से पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आया, लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद हाई कोर्ट में अपील की गई, जहाँ से फिर संगठन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को तुरंत एरियर्स भुगतान के निर्देश दिए गए।₹सरकार की हठधर्मिता और पूर्व नियोजित योजना के चलते अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है, ताकि प्रकरण लंबित रहे। सरकार चाहती है कि 'दाल में नमक' के बराबर बचे ये बुजुर्ग दावेदार समय के साथ कम होते जाएं और उन्हें भुगतान न करना पड़े।

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सामाजिक समानता, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना-बुधपाल सिंह

समान नागरिक संहिता सुझाव अभियान को बनाएं जनआंदोलन-कलेक्टर

अनूपपुर। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य शासन द्वारा प्रकिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में उच्च स्तरीय समिति की ओर से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूसीसी के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य बुधपाल सिंह ने संहिता के प्रावधानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों से संहिता को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए सुझाव एवं विचार प्राप्त किए गए। बैठक को संबोधित करते हुए समिति सदस्य बुधपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में निहित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक समानता, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने इसके ऐतिहासिक संदर्भों को रेखांकित करते हुए बताया कि गोवा में यह व्यवस्था आजादी के पूर्व से ही प्रभावी रूप से लागू है। वर्तमान में उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के बाद मध्यप्रदेश भी इसे लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसा करने वाला यह देश का चौथा राज्य होगा। समिति सदस्य ने समाज के विभिन्न वर्गों की आशंकाओं और संशयों को दूर करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था में जनजातीय समुदाय की विशिष्ट परंपराओं, संस्कृति और रीति-रिवाजों का पूरा सम्मान किया गया है, जिसके चलते अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि यूसीसी के लागू होने से किसी भी धर्म की पूजा-पद्धति, धार्मिक गतिविधियों या नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि यह कानून केवल

सामाजिक और नागरिक सुधारों तक ही सीमित है। वर्तमान कानूनी विसंगतियों पर चर्चा करते हुए बुधपाल सिंह ने बताया कि अभी विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण (गोद लेना) और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के अधीन आते हैं। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य इन सभी विषयों पर एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं को समाज में पुरुषों के समकक्ष समान अधिकार मिल सकें। संहिता के लागू होने से विवाह का अनिवार्य पंजीकरण होगा, बेटे-बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, गोद लेने की प्रक्रिया पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होगी और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी रोक लगेगी।

इस विचार-विमर्श सत्र में उपस्थित नागरिकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। वक्ताओं ने विशेष रूप से विवाह की आयु, भरण-पोषण की राशि और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमन के लिए बनाए जाने वाले प्रावधानों में पूर्ण स्पष्टता रखने पर जोर दिया। इसके साथ ही, आमजन तक इस कानून की सही जानकारी पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव भी दिया गया ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम या अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। बैठक में जिला पंचायत सदस्य रंजीत सर्राटी, नगर पालिका परिषद अनूपपुर की उपाध्यक्ष श्रीमती सोनाली तिवारी, नगर परिषद डूमर कछार के अध्यक्ष सुनील कुमार चौरसिया, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष परिहार, सामाजिक कार्यकर्ता सुशील शर्मा, विजय सिंह, निखिल कुमार, मुकेश गौतम, राकेश द्विवेदी सहित अन्य गणमन नागरिकों ने भी समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव दिए। बैठक में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि शासन स्तर पर गठित यह उच्च स्तरीय समिति प्रत्येक जिले में जाकर नागरिकों से सीधा संवाद कर रही है। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों, सामुदायिक संगठनों और आम नागरिकों से अपील की कि वे आने वाले अंतिम पांच दिनों में इस प्रक्रिया को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दें। जो लोग आज बैठक में शामिल नहीं हो सके, वे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने ऑनलाइन सुझाव दर्ज कराएं, ताकि समाज के हर वर्ग के विचारों को समाहित करते हुए एक सर्वसमावेशी और न्यायसंगत फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर कमलेश पुरी, अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी अनूपपुर सुश्री प्राशि अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य रंजीत सर्राटी, नगर पालिका अनूपपुर अध्यक्ष श्रीमती अंजुलिका सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती सोनाली तिवारी, नगर परिषद डूमरकछार अध्यक्ष सुनील चौरसिया, नगर परिषद वनगवां (अमलाई) गीता गुप्ता, नगर पालिका बिजुरी की अध्यक्ष श्रीमती सहबिन पनिका, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद उमेश पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग विनोद परस्ते सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी ,जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी, पत्रकार उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

अवैध कोयले के परिवहन पर बिजुरी पुलिस की कार्यवाही

बिजुरी। जिले में अवैध गतिविधियों और खनिज माफियाओं के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध रूप से चोरी का कोयला परिवहन करते हुए एक ओम्नी कार चालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 13-14 जून की दरमियानी रात को बिजुरी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने बिजुरी गुलाब ग्राउंड के पास घेराबंदी की और एक संदेही ओम्नी कार को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 32 बोरी अवैध कोयला लोड पाया गया। वाहन चालक की पहचान राजेश प्रजापति उर्फ सरदार (उम्र 38 वर्ष) निवासी सीएमपीडीआई कैम्प, बिजुरी के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान चालक ने स्वीकार किया कि वह यह कोयला रामनगर से चोरी कर बिजुरी में बेचने के उद्देश्य से ला रहा था। कोयले के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या खनिज रॉयल्टी पर्ची पेश न करने पर पुलिस ने वाहन और कोयले को जप्त कर लिया।जप्त सामग्री की अनुमानित अवैध चोरी का कोयला (32 बोरी) 5,000, ओम्नी कार 2,00,000 कुल जप्त मशरूका' 2,05,000 पुलिस ने आरोपी चालक राजेश प्रजापति के विरुद्ध थाना बिजुरी में अपराध क्रमांक 213/2026 धारा 303(2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) एवं 4/21 खनिज अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे हिरासत में ले लिया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बिजुरी निरीक्षक विकास सिंह, सहायक उप निरीक्षक रविकरण पयासी और आरक्षक रवि सिंह की उल्लेखनीय एवं सराहनीय भूमिका रही।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई 660 मेगावाट की इकाई स्थापना के दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि

चचाई। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 210 मेगावाट इकाई स्थापना के बाद से चली आ रही बहुप्रतिक्षित 660 मेगावाट प्लांट की मांग कई वर्षों बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रयासों से आज एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हुआ है 660 मेगावाट प्लांट बनाने का जिम्मा बीएचईएल इंडिया कंपनी को मिलने के बाद विगत 12 जून को परियोजना के मुख्य बॉयलर क्षेत्र में कंपनी व ताप विद्युत गृह के अधिकारियों द्वारा विधि विधान से उत्खनन कार्य का शुभारंभ किया गया जो परियोजना को साकार रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है इससे पूर्व ताप विद्युत गृह प्रबंध के विशेष प्रयासों से उनकी टीम द्वारा स्विच यार्ड के बे--1 से बे--5 क्षेत्र को रिकार्ड समय में खाली करा कर परियोजना के लिए तैयार किया गया जिससे निर्माण गतिविधियों को समयबद्ध गति दी जा सके। परियोजना के बॉयलर क्षेत्र के उद्घाटन के अवसर पर ताप विद्युत ग्रहों के कार्यपालक निदेशक (उत्पादन) तनवीर अहमद, परियोजना निदेशक (बीएचईएल) अमरेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (संचालन एवं संधारण) विजय देव, अधीक्षण अभियंता (सेवाएं) एस पी निषाद, अशोक कुमार खरे, रुद्र शरण मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होकर इस बड़ी परियोजना के प्रारंभ के साक्षी बने जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्षमताओं को भविष्य में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

लापरवाही पर प्रधान आरक्षक निलंबित, दो एएसआई की भूमिका जांच के घेरे में

पुलिस हिरासत से आरोपी फरार, अनूपपुर पुलिस में मचा हड़कंप

अनूपपुर। अनूपपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा से एक संदेही आरोपी के फरार होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। चचाई थाना पुलिस द्वारा विवेचना के लिए हिरासत में लिया गया आरोपी मंगेश सिंह पुलिस की निगरानी से भाग निकला। घटना को गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रान्त मुराब ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक मोहन सिंह को निलंबित कर दिया है, जबकि दो सहायक उपनिरीक्षकों की भूमिका की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस हिरासत को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अनूपपुर जिले में घटी एक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना चचाई पुलिस द्वारा चोरी से जुड़े एक मामले में संदेही आरोपी मंगेश सिंह को पूछताछ एवं माल बरामदगी के लिए अभिरक्षा में लिया गया था। आरोपी को तीन पुलिसकर्मियों की निगरानी में ले जाया जा रहा था, लेकिन थाना अमलाई क्षेत्र में जांच के दौरान वह हथकड़ी सहित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त मुराब ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अनुशासनात्मक

कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर प्रधान आरक्षक मोहन सिंह को निलंबित कर दिया गया, वहीं आरोपी को निगरानी में छोड़कर गए दोनों एएसआई की भूमिका की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। अब पुलिस के सामने आरोपी की गिरफ्तारी और विभागीय जवाबदेही दोनों बड़ी चुनौतियां बन गई हैं।

चोरी के मामले में पुलिस अभिरक्षा में था आरोपी

थाना चचाई में दर्ज अपराध की विवेचना के दौरान संदेही आरोपी मंगेश सिंह निवासी टिकरीटोला, बुढ़ार को 15 जून को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। पुलिस को उससे माल बरामदगी और चोरी के मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जुटानी थी। आरोपी को एएसआई प्यारेलाल सिंह, एएसआई लालमणि चौधरी और प्रधान आरक्षक मोहन सिंह की निगरानी में रखा गया था। पुलिस को उम्मीद थी कि आरोपी से पूछताछ के बाद मामले में महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही वह पुलिस की पकड़ से निकल गया है।

अमलाई थाना परिसर के बाहर हुआ पूरा घटनाक्रम

जानकारी के अनुसार विवेचना टीम थाना अमलाई क्षेत्र पहुंची थी, जहां चोरी की गाड़ियों और उनके कलपुर्जों की तस्दीक की जानी थी। इस दौरान दोनों एएसआई जांच कार्य के लिए अमलाई थाना परिसर के भीतर चले गए, जबकि आरोपी को वाहन में प्रधान आरक्षक मोहन सिंह की निगरानी में छोड़ दिया गया। वाहन थाना परिसर के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद जब अधिकारी लौटे तो आरोपी वहां मौजूद नहीं मिला। इसके बाद पुलिसकर्मियों के बीच अफरा-तफरी मच गई और तत्काल उसकी तलाश शुरू की गई है।

हथकड़ी सरकाकर भागने का दावा

घटना के बाद पूछताछ में प्रधान आरक्षक मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपनी कलाई से हथकड़ी सरका ली और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। हालांकि इस दावे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर पुलिस अभिरक्षा में रखे गए आरोपी पर लगातार निगरानी रखी जाती है, ऐसे में आरोपी का भाग निकलना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक माना जा रहा है। विभागीय जांच में यह भी देखा जाएगा कि हथकड़ी लगाने और निगरानी के दौरान कौन-कौन सी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

एसपी ने दिखाई सख्ती, तत्काल निलंबन

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विक्रान्त मुराब ने पूरे मामले की समीक्षा की। प्रथम दृष्टया आरोपी की सुरक्षा में घोर लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता मानते हुए प्रधान आरक्षक मोहन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र अनूपपुर संबद्ध कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की इस कार्यवाही को विभाग में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में सख्त संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस अभिरक्षा से आरोपी का फरार होना बेहद गंभीर मामला है, जिसे किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

दो एएसआई की भूमिका भी जांच के दायरे में

मामले में केवल प्रधान आरक्षक ही नहीं, बल्कि विवेचक एएसआई प्यारेलाल सिंह और एएसआई लालमणि चौधरी की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है। पुलिस अधीक्षक ने दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी को वाहन में छोड़कर दोनों अधिकारियों का अलग जाना कितना उचित था और क्या उन्होंने सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन किया था। विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। वहीं दूसरी ओर फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

बिना परमिट संचालित वाहनों पर प्रभारी परिवहन चेक पॉइंट अनूपपुर 2 की सख्त कार्रवाई

290.200 रूपये कि राजस्व वसूली

अनूपपुर। अनूपपुर जिले में उमेश जोगा परिवहन आयुक्त ग्वालियर मध्यप्रदेश के निर्देश पर हर्षल पंचोली कलेक्टर अनूपपुर के आदेश पर एवं सुरेंद्र सिंह गौतम जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर के मार्गदर्शन पर समय- समय पर परीवहन विभाग द्वारा परिवहन नियमों के विरुद्ध उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई की जाती रही है। गौरव दीक्षित (प्रभारी) चेकप्वाइंट अनूपपुर-2 ने अपनी टीम के साथ अनूपपुर से पेंड्रारोड मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कई भारी मालयान वाहने एवं यात्री बसों को मार्ग पर रोका गया। जांच में बिना वैध परमिट के कई संचालित मालयान वाहने मौके से पायी गयी। सभी मालयान वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। जिसमें 24200 रूपये कर कि राशि, 188000 रूपये शास्ति ,78000 रूपये का शमन शुल्क प्राप्त कर। इस विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 2,90,200 (दो लाख नब्बे हजार दो सौ रुपये) का राजस्व शासन को एक ही दिन में प्राप्त हुआ। कार्रवाई के दौरान अन्य मालयान वाहनों एवं यात्री बसों के भी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। प्रभारी परिवहन चेक पॉइंट द्वारा मार्ग के समस्त वाहन चालकों को परिवहन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं। बॉर्डर चेकपोस्ट बंद होने के बाद कर यात्री बसों, मालयान वाहनों में कर अपवंचन (टैक्स चोरी) अवैध परिवहन, ओवरलोड, के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। मध्यप्रदेश में गुजरात मॉडल के आधार पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। बिना परमिट, बिना टैक्स, ओवरलोड वाहनों, को मोटरयान नियमो के तहत विभिन्न धाराओं के तहत वाहनों कि जांच की जा रही है। आरटीओ चेक प्वाइंट 2, अनूपपुर के द्वारा लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा हैं। चेकप्वाइंट प्रभारी गौरव दीक्षित ने स्पष्ट किया कि, जिले के भीतर बिना यात्री बसों, मालयान वाहनों पर बिना परमिट, ओवरलोड, बिना बीमा, बिना फिटनेस, टैक्स बकाया एवं कर अपवंचन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मध्यप्रदेश शासन तथा परिवहन विभाग के राजस्व की हानि को रोका जा सके।

चित्रकूट धाम से आए 72 वर्षीय बुजुर्ग संत ने 2 घंटे बिताए मड़फा तालाब सामतपुर में शवासन मुद्रा में

अनूपपुर। योग साधक संत रामसखा पांडेय चित्रकूट धाम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ठीक 11.00 बजे पूजा अर्चना कर मड़फा तालाब सामतपुर में शवासन मुद्रा में पूरे 2 घंटे बिताए। ठीक 1.00 बजे वह तालाब से बाहर आए। जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग मड़फा तालाब सामतपुर में पहुंचे। एसडीईआरएफ की टीम पूरी व्यवस्था के साथ वहां पर उपस्थित रही। ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके। अनूपपुर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी के पुजारी ब्रह्मानंद गर्ग ने जय घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कराई। देखते ही देखते संत शवासन मुद्रा में तालाब में लेट गए। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली देखने वालों का हुजूम तालाब पहुंचने लगा और पूरे समय तक जब तक वह तालाब में लेटे थे लोगों की निगाह उन्हीं के ऊपर थी। योग साधक रामसखा पांडेय 2 घंटे बाद तालाब से बाहर निकले। उनके बाहर निकलते ही दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पुजारी ब्रह्मानंद गर्ग ने नारियल देकर उनका सम्मान किया। वही नगर के नागरिक पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने उनका माल्यार्पण

कर स्वागत किया। संत तालाब से निकलने के बाद उपस्थित लोगों को बताया कि आधुनिक जीवनशैली में इंसान लगातार तनाव और बीमारियों से जूझ रहा है।ऐसे समय में योग ही एक ऐसा साधन है, जो तन-मन को संतुलित कर हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि देशभर में भ्रमण कर योग की शक्ति का संदेश दे रहे हैं। उनका मानना है योगाभ्यास से न केवल मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती मिलती है,बल्कि तनाव और बीमारियों से भी बचाव होता है। उन्होंने कहा कि योग और आसन से हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है।जिन लोगों को हम स्वस्थ समझते हैं, वे भी पूर्णतः रोग मुक्त नहीं हैं।वे शारीरिक रूप से भले ही रोगी न हों,लेकिन मानसिक रूप से रोगी होते हैं। योग चिकित्सा का परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता है, लेकिन यह स्थाई रूप से लाभ पहुंचाता है। वर्तमान समय में लोग तनाव और बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में योग से तन और मन को संतुलित कर हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिलती है। जल संरक्षण एवं पर्यावरण का संदेश उन्होंने सभी को दिया। उन्होंने कहा कि योग ही एक ऐसा साधन है,जो तन-मन को संतुलित कर हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।

सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों ने परियोजना के जल्द आने के पक्ष में दिया समर्थन

लामाटोला भूमिगत खदान की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई सफलतापूर्वक सम्पन्न

अनूपपुर। जिले की कोतमा तहसील अंतर्गत प्रस्तावित लामाटोला भूमिगत कोयला खदान परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई बुधवार को ग्राम पंचायत बसखली स्थित शासकीय हाई स्कूल परिसर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में परियोजना से प्रभावित सात गांवों के लगभग 1,500 ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा परियोजना के पक्ष में अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। लोक सुनवाई का संचालन कोतमा के अनुविभागीय अधिकारी सतीश वर्मा एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डॉ. अशोक कुमार तिवारी की उपस्थिति में किया गया। लोक सुनवाई में लामाटोला, रेउला, गढ़ी, बिचारपुर, बसखली, मौहारी एवं थोड़हा गांवों के ग्रामीणों ने परियोजना के संभावित सामाजिक एवं आर्थिक लाभों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों के सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उन्हें अभिलेख में दर्ज किया। परियोजना के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित खदान के लिए अपनाए जाने वाले पर्यावरणीय संरक्षण उपायों एवं प्रबंधन योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी। ए.सी.सी. लिमिटेड की तरफ से कई अधिकारियों की मौजूदगी रही जिन्होंने परियोजना के लिए उठाये जानेवाले पर्यावरणीय उपायों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। लामाटोला भूमिगत कोयला परियोजना भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक खनन के अंतर्गत अगस्त 2024 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड को आवंटित की गई है। यह परियोजना अनूपपुर जिले की कोतमा तहसील के सात गांवों में लगभग 1,030 हेक्टेयर क्षेत्र में

विस्तृत है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, जल संसाधन, ध्वनि स्तर, भूमि पर्यावरण एवं मृदा गुणवत्ता सहित विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अध्ययन में सभी मानक निर्धारित सीमाओं के अनुरूप पाए गए हैं तथा परियोजना के लिए व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजना का भी प्रावधान किया गया है।

यह परियोजना लगभग 35 वर्षों तक संचालित होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रतिवर्ष 20 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। परियोजना के संचालन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही, राज्य सरकार के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। ए.सी.सी. लिमिटेड ने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कौशल विकास एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने भी परियोजना से क्षेत्र के समग्र विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की। कोतमा के जनपद उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने इस परियोजना का स्वागत करते हुए बताया कि, इस परियोजना के आने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं क्षेत्र का विकास होगा। जबकि बसखला के जनपद सदस्य देवनाथ सिंह का कहना है कि, इस परियोजना के संचालित होने से रोजगार के अवसर आएंगे एवं मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा। बसखला गांव की रहने वाली गणेशिया सिंह कहती हैं कि, लामाटोला प्रोजेक्ट के आने से इस क्षेत्र का विकास होगा। परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमित जल छिड़काव, व्यापक वृक्षारोपण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, वर्षा जल संचयन तथा खनन पट्टा क्षेत्र एवं परिवहन मार्गों के किनारे हरित पट्टियों का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ जनस्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सतत आजीविका, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं किसान विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय समुदाय के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।

यातायात नियमों के पालन हेतु जिले में चलाया जाए विशेष अभियानः पुलिस अधीक्षक

सड़क दुर्घटनाओं को रोकना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता- कलेक्टर

अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराव की उपस्थिति में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व में आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री पंचोली ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी निर्माण एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इस दिशा में सभी विभागों को सक्रिय एवं जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में संचालित ओवरलोड वाहनों पर विशेष निगरानी रखने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है, इसलिए इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यूनतम किया जाए, जिससे आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराव ने कहा कि जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन हेतु विशेष जनजागरूकता अभियान संचालित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यातायात नियमों के पालन तथा हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा जनहानि को रोकने के

लिए नागरिकों द्वारा यातायात नियमों का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आमजन से वाहन चलाते समय हेलमेट का नियमित उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि हेलमेट न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन भी है। उन्होंने संबंधित विभागों को जनजागरूकता के साथ-साथ नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यातायात विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में पूर्व में चिन्हित 11 ब्लैक स्पॉट्स में से अधिकांश स्थानों पर सड़क सुरक्षा संबंधी सुधारात्मक कार्यों एवं दुर्घटनाओं में कमी आने के कारण उन्हें ब्लैक स्पॉट की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में केवल 4 ब्लैक स्पॉट शेष हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं। विभाग द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2026 में अब तक जिले में 187 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 232 व्यक्ति घायल हुए हैं तथा 71 लोगों की मृत्यु हुई है। इस पर कलेक्टर श्री पंचोली ने दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में डिप्टी कलेक्टर कमलेश पुरी, जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह गौतम, यातायात प्रभारी विनोद दुबे सहित अन्य संबंधित विभाग के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बिजुरी नगर पालिका का लोक कल्याण शिविर बना जनसेवा का केंद्र

बिजुरी। नगर पालिका परिषद बिजुरी द्वारा बुधवार को लोक कल्याण शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर में आम नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। शिविर का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की

जनहितैषी सोच और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुरूप किया गया। इस दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं से वंचित लोगों की समस्याएं सुनी गईं तथा उनके त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद बिजुरी की अध्यक्ष शहबीन पनिका ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। वहीं उपाध्यक्ष प्रीति सतीश शर्मा ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन साहू ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि दीपक शर्मा, उपयंत्री देवल सिंह सहित नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन तक शासन की योजनाओं को सरलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाना रहा। लोक कल्याण शिविर के सफल आयोजन से नागरिकों में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने शासन एवं प्रशासन की इस पहल की सराहना की। नगर पालिका परिषद बिजुरी द्वारा भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी शिविर आयोजित किए जाने की बात कही गई।